



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2008/फाल्गुन 27, 1929

No. 119]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2008/PHALGUNA 27, 1929

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

सा.का.नि. 185(अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ड की उप-धारा (4ख) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2008 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 में,—
(क) विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. किसी न्यायपीठ द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों को विनिर्दिष्ट करने की अध्यक्ष की शक्ति.—(1) अध्यक्ष के लिए यह उपबंध करना विधिपूर्ण होगा कि अधिनियम की धारा 247, धारा 250, धारा 269 और धारा 388ख के अंतर्गत आने वाले विषय और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2क के अधीन आने वाले विषयों का निपटारा एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली प्रधान न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली में स्थित होगी किंतु यह अपने स्वविवेक से या सभी पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर भारत में किसी अन्य स्थान पर भी बैठ सकेंगी।

(3) अध्यक्ष के लिए यह उपबंध करना विधिपूर्ण होगा कि इस अधिनियम की अन्य सभी धाराओं के अंतर्गत आने वाले विषयों का निपटारा प्रादेशिक न्यायपीठों अर्थात्

नई दिल्ली न्यायपीठ, चेन्नई न्यायपीठ, कोलकाता न्यायपीठ और मुम्बई न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा जो एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेंगी :

परंतु यह कि तारीख 1 अप्रैल, 2008 को प्रधान न्यायपीठ और अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ के समक्ष लंबित विषयों का निपटारा क्रमशः प्रधान न्यायपीठ और अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ के नाम से किया जाता रहेगा :

परंतु यह और कि विनियम 7 में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह या सभी पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर या अन्य कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं प्रादेशिक न्यायपीठों के समक्ष लंबित मामलों को प्रधान न्यायपीठ को अंतरित करें।

(ख) विनियम 7 में —

- (i) उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रादेशिक न्यायपीठों की भौगोलिक अधिकारिता के अधीन आने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुलग्नक-1 में उपबंधित हैं;

- (ii) उप विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रादेशिक न्यायपीठों सामान्यतया अपनी बैठकें कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और नई दिल्ली में करेंगी :

परंतु यह कि न्यायपीठें स्वविवेक से अपनी-अपनी भौगोलिक अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी अन्य शहर या नगर में या पक्षकारों की सहमति से उनकी अधिकारिता से बाहर किसी अन्य स्थान पर बैठकें कर सकेंगी”;

(ग) विनियम 34 में उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) प्रधान न्यायपीठ या प्रादेशिक न्यायपीठों के समक्ष याचिका या आवेदन फाइल करने के संबंध में इन विनियमों के अधीन संदेय फीस का संदाय वेतन और लेखा अधिकारी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, यथास्थिति, नई दिल्ली या कोलकाता या मुंबई या चेन्नई के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से किया जाएगा।”

(घ) अनुलग्नक-1 में,—

- (i) क्रम संख्यांक 1 में, “पूर्वी क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “कोलकाता न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्यांक 2 में, “उत्तरी क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “नई दिल्ली न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्यांक 3 में, “दक्षिणी क्षेत्र (अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ)” शब्दों के स्थान पर, “चेन्नई न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्यांक 4 में, “पश्चिमी क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “मुंबई न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) अनुलग्नक-2 में,—

- (i) फार्म संख्यांक 1 में “अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) फार्म संख्यांक 3 में “अतिरिक्त प्रधान न्यायपीठ” शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) फार्म संख्यांक 4 में विद्यमान टिप्पण-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
“टिप्पण 1 :—आवेदन के साथ “वेतन और लेखा अधिकारी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, यथास्थिति, नई दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या चेन्नई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से फीस केवल पचास रुपए लगी होगी”।”

[फा. सं. 10/36/2001-सीएलबी]

बी. एल. सिन्हा, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 29(अ) तारीख 31 मई, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए—

- (1) सं. सा.का.नि. 492(अ), तारीख 14 मई, 1992
- (2) सं. सा.का.नि. 593(अ), तारीख 25 जुलाई, 1994
- (3) सं. सा.का.नि. 394(अ), तारीख 2 मई, 1995
- (4) सं. सा.का.नि. 433(अ), तारीख 1 अगस्त, 1997
- (5) सं. सा.का.नि. 917(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2000
- (6) सं. सा.का.नि. 437(अ), तारीख 15 जून, 2001
- (7) सं. सा.का.नि. 929(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001
- (8) सं. सा.का.नि. 619(अ), तारीख 5 सितम्बर, 2002

COMPANY LAW BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2008

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) and sub-section (6) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby makes the following regulations further to amend the Company Law Board Regulations, 1991, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Company Law Board (Amendment) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2008.
2. In the Company Law Board Regulations, 1991,—
(a) for regulation 4, the following shall be substituted, namely :—

“4. Power of the Chairman to specify matters which may be dealt with by a Bench.—(1) It shall be lawful for the Chairman to provide that matters falling under Sections 247, 250, 269 and 388B of the Act and under Section 2A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) shall be dealt with by the Principal Bench consisting of one or more Members.

(2) The Principal Bench shall be at New Delhi but it may sit at any other place in India at its discretion or at the joint request of all the parties.

(3) It shall be lawful for the Chairman to provide that matters falling under all other sections of the Act shall be dealt with by Regional Benches, namely, New Delhi Bench, Chennai Bench, Kolkata Bench and Mumbai Bench, consisting of one or more Members :

Provided that matters pending before the Principal Bench and Additional Principal Bench as on 1st day of April, 2008 shall continue to be disposed of in the name of Principal Bench and Additional Principal Bench respectively :

Provided further that notwithstanding anything contained in regulation 7, it shall be lawful for the Chairman to transfer any matter pending before the Regional Benches to the Principal Bench either at the joint request of all the parties or for other reasons to be recorded in writing.

(b) in regulation 7—

- (i) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

“The States or Union-territories falling under the geographical jurisdiction of the Regional Benches shall be as provided in Annexure-I;

- (ii) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :—

"The Regional Benches shall ordinarily have their sittings at Kolkata, Mumbai, Chennai and New Delhi :

Provided that the Benches may, at their discretion, hold sittings in any other city or town falling within their respective geographical jurisdiction or any other place outside their jurisdiction with the consent of the parties";

(c) in regulation 34, for sub-regulation (3), the following shall be substituted namely :—

"(3) In respect of a petition or application filed before the Principal Bench or other Regional Benches, fees payable under these regulations shall be paid by means of a bank draft or bankers cheque drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi or Kolkata or Mumbai or Chennai, as the case may be.

(d) in Annexure-I, —

- (i) in serial number 1, for the words "Eastern Region", the words, "Kolkata Bench", shall be substituted;
- (ii) in serial number 2, for the words, "Northern Region", the words, "New Delhi Bench" shall be substituted;
- (iii) in serial number 3, for the words "Southern Region (Additional Principal Bench" the words "Chennai Bench" shall be substituted;
- (iv) in serial number 4, for the words, "Western Region" the words "Mumbai Bench" shall be substituted;

(e) In Annexure-II, —

- (i) in Form No.1, the words "Additional Principal Bench" shall be omitted;
- (ii) In Form No. 3, the words "Additional Principal Bench" shall be omitted;
- (iii) In Form No. 4, for the existing Note 1, the following shall be substituted namely :—

"Note 1.— The application shall be accompanied by a fee of rupees fifty only by way of bank draft or bankers cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi or Mumbai or Kolkata or Chennai as the case may be"."

[F. No. 10/36/2001-CLB]

B. L. SINHA, Secy.

Note : The Principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 29(E), dated the 31st May, 1991 and subsequently amended by—

- (1) No. G.S.R. 492(E), dated the 14th May, 1992
- (2) No. G.S.R. 593(E), dated the 25th July, 1994
- (3) No. G.S.R. 394(E), dated the 2nd May, 1995
- (4) No. G.S.R. 433(E), dated the 1st August, 1997
- (5) No. G.S.R. 917(E), dated the 14th December, 2000
- (6) No. G.S.R. 437(E), dated the 15th June, 2001
- (7) No. G.S.R. 929(E), dated the 31st December, 2001
- (8) No. G.S.R. 619(E), dated the 5th September, 2002